Result Mitra Daily Magazine

वैश्विक बेरोजगारी के बदलते रुझान

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक नई रिपोर्ट (विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य) के अनुसार, नए अनुमानों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2024 की वैश्विक बेरोजगारी में मामूली गिरावट आएगी, हालांकि श्रम बाजारों में असमानताएं बनी हुई हैं, और निम्न आय वाले देशों में महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित होंगी।
- हालांकि आईएलओ ने इस वर्ष जनवरी माह में अनुमान लगाया था कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में अपेक्षित वृद्धि के कारण बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ जाएगी।
- अपितु नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में बेरोजगारी की दर में गिरावट की प्रवृत्ति स्थिर होने की उम्मीद है, और बेरोजगारी 4.9 प्रतिशत पर बनी रहेगी, जो 2023 में 5.0 प्रतिशत से कम है।
- इस दृष्टिकोण के बावजूद, रिपोर्ट रोजगार के अवसरों की निरंतर कमी को रेखांकित करती है।
- आईएलओ का अनुमान है कि 'रोजगार का अंतर' - जो बिना नौकरी वाले लेकिन काम करना चाहते लोगों की संख्या को मापता है - 2024 में 402 मिलियन लोगों तक पहुंच जाएगा। इसमें 183 मिलियन लोग शामिल हैं जिन्हें बेरोजगार माना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नई रिपोर्ट का सार

- आईएलओ की रिपोर्ट के विस्तृत आंकडों से ज्ञात होता है कि महिलाएँ, खास तौर पर कम आय वाले देशों में, अवसरों की कमी से असमान रूप से प्रभावित हैं। कम आय वाले देशों में महिलाओं के लिए नौकरियों का अंतर 22.8 प्रतिशत तक पहुँच जाता है, जबकि पुरुषों के लिए यह 15.3 प्रतिशत है। यह उच्च आय वाले देशों से अलग है, जहाँ महिलाओं के लिए यह दर 9.7 प्रतिशत और पुरुषों के लिए 7.3 प्रतिशत है।

- वैश्विक स्तर पर, 2024 में कामकाजी उम्र की 45.6 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत हैं, जबकि पुरुषों में यह 69.2 प्रतिशत है।
- यहां तक कि जब महिलाएं रोजगार में होती हैं, तब भी वे पुरुषों की तुलना में बहुत कम कमाती हैं, खासकर कम आय वाले देशों में। जबकि उच्च आय वाले देशों में महिलाएं पुरुषों द्वारा कमाए गए एक डॉलर की तुलना में तिहत्तर सेंट कमाती हैं, वहीं कम आय वाले देशों में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ़ चालीस सेंट रह जाता है।
- रिपोर्ट का सारतत्व है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, गरीबी और असमानता को कम करने के लिए "एक व्यापक दृष्टिकोण" की तत्काल आवश्यकता है।

बदलते रुझान

- वर्ष 2024 के पहले महीनों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि अपेक्षा से थोड़ी अधिक मजबूत रही है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि मुद्रास्फीति कम हो रही है, जिससे घरेलू आय को राहत मिली है।
- अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक विकास के लिए अपने 2024 के पूर्वानुमान को जनवरी में अनुमानित 3.1% से बढ़ाकर 3.2% कर दिया, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी परिदृश्य में सुधार था।
- आईएलओ के अनुसार, "समष्टि आर्थिक परिवेश में यह स्थिरता अपेक्षाकृत स्थिर श्रम बाजार परिदृश्य में परिवर्तित हो रही है।"
- हालांकि, मध्यम अवधि में स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मौद्रिक और राजकोषीय नीति समायोजन अपेक्षित हैं तथा प्रतिबंधात्मक वृहद आर्थिक नीतियों का श्रम बाजार पर विलंबित प्रभाव पड़ रहा है।

विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य

- इसी वर्ष जनवरी माह में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य: रुझान 2024 नामक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी और बढ़ती असमानताएं तथा स्थिर उत्पादकता चिंता का कारण हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बावजूद, वैश्विक श्रम बाजारों ने आश्चर्यजनक लचीलापन दिखाया है, जिसमें बेरोजगारी दर और नौकरी अंतराल दर (नौकरी खोजने में रुचि रखने वाले बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या) दोनों में सुधार हुआ है।
- यद्यपि विश्व में कोरोना महामारी से उबरने की प्रक्रिया असमान है, नई कमजोरियां और अनेक संकट अधिक सामाजिक न्याय की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं।
- बेरोजगारी दर और रोजगार के अंतर की दर के संदर्भ में उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच फ़ासला अधिक है।
- अपितु वर्ष 2023 में उच्च आय वाले देशों में रोजगार के अंतर की दर 8.2% थी, जबकि निम्न आय वर्ग में यह 20.5% थी।

भारत में बेरोजगारी के हालिया रुझान

- स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023" रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर 2017-18 में 8.7% से घटकर 2021-22 में 6.6% हो गई।
- वर्ष 2021-22 में भारत के 25 वर्ष से कम आयु के 42% से अधिक स्नातक बेरोजगार थे।
- अपितु महामारी के बाद, 60% महिलाएं स्वरोजगार में हैं, जबकि महामारी से पहले यह संख्या 50% थी।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की तुलना में सामान्य जातियों के अधिक लोग आकस्मिक श्रम से बाहर निकले हैं।
- वर्ष 2021 में, 40% अनुसूचित जाति श्रमिक आकस्मिक रोजगार में थे, जबकि 22% नियमित वेतन वाले श्रमिक थे।
- ध्यातव्य है कि आर्थिक विकास के कारण भारत में औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि नहीं हुई है।
- कृषि क्षेत्र से बाहर जाने वाले श्रमिकों को अक्सर औपचारिक नौकरियों की बजाय अनौपचारिक और संविदात्मक रोजगार में रखा जाता है।

ResultMitra

बेरोजगारी की हालिया प्रवृत्तियों हेतु उत्तरदायी कारक

- स्वचालन और तकनीकी उन्नति कुछ नौकरियों का स्थान ले सकती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, जब तक कि श्रमिकों को नई भूमिकाओं के लिए पुनः प्रशिक्षित नहीं किया जाता।
- श्रम कानून, कराधान और व्यवसाय विनियमन से संबंधित नीतियां रोजगार सृजन और बेरोजगारी दर को प्रभावित करती हैं।
- आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान रोजगार सृजन में कमी आ सकती है और छंटनी हो सकती है, जिससे बेरोजगारी दर बढ़ सकती है।
- नियोक्ताओं द्वारा मांगे गए कौशल और नौकरी चाहने वालों के पास मौजूद कौशल के बीच बेमेल के परिणामस्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी हो सकती है।
- विशेषकर भारत के संबंध में, देश की विशाल जनसंख्या, मूलतः युवा जनसंख्या, कार्यबल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में चुनौतियां उत्पन्न करती है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- यह इस विचार को व्यक्त करने के लिए स्थापित किया गया था कि सामाजिक निष्पक्षता किसी भी दीर्घकालिक, वैश्विक शांति की आधारशिला होनी चाहिए।
- इसे 1919 में वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया था।
- वर्ष 1946 में, इसे संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में नामित किया गया।
- यह एक त्रिपक्षीय संगठन है, और अपनी तरह का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कंपनियों, श्रम और सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निकायों को एकजुट करता है।
- भारत 187 सदस्य देशों वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है।
- भारत ने 2020 में ILO गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
- स्विट्जरलैंड का जिनेवा में इसका मुख्यालय है।
- सभ्य रोजगार को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय भाईचारे और शांति को बढ़ावा देने के लिए, आईएलओ को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

Result Mitra